देश में महत्वपूर्ण बौद्ध केन्द्रों/स्थानों की सूची

राज्य का नाम	केन्द्र
1. आन्ध्र प्रदेश	1. अमरावती
	2. बावीकोंडा
	3. भट्टीपरोलू
	4.चन्दावरम
	5. घंटासाला
	6. गुंटुपल्ली
	7. जगैयापेटा
	8. मॉगामारीपेटा
	9. नागार्जुनकोंडा
	10. नेलाकोंडापल्ली
	11. फानीगिरि
	12. रामतीर्थम
	13. शंकरम
	14. सालीहुंडम
2. अरूणाचल प्रदेश	1. तवांग
3. असम	1. हाजो
4. बिहार	1. बोधगया
	2. लौरिया नन्दनगढ़
	3. नालन्दा
	4. पटना
	5. राजगीर
	6. वैशाली
5. गुजरात	1. देवनीमोरी
	2. साना
	3. तालाजा
6. हिमाचल प्रदेश	1. बीर
	2. चांगो
	3. गुरू घंटाल
	4. कारडांग
	5. क्ये
	6. मक्लियोडगंज
	7. रेवालसर
	8. टाबो
	9. ताशीजोंग
	10. त्रिलोकनाथ
7. जम्मू व कश्मीर	1. अल्ची
	2. हैमित
	3. कार्शा
	4. लामायुरू
	5. मल्बेक
	6. फुगताल
	7. रंगडम
	8. सानी
8. कर्नाटक	1. काहरे
	2. सन्नाती
9. केरल	1. करांगानोर
	2. गौतमपुरम
	3. करुणादिकुट्टन
	4. कृष्णापुरम
	5. माडायी
	6. मावेलीकारा
	7. नागालासेरी
10. मध्य प्रदेश	1. सांची
11. महाराष्ट्र	1. अजन्ता
	2. औरंगाबाद
	3. बेडसा
	4. भांजा
	5. एलौरा
	6. कनहेरी
	7. कार्ली
	8. पिटालखोरा
12. उड़ीसा	1. धौली
	2. ललित गिरि
	3. रत्नागिरि
	4. उदयगिरि
13. पंजाब	1. संघोल
14. राजस्थान	1. बिन्नायागा
	2. कोल्वी
15. सिक्किम	1. पेमायांगत्से
	2. फोडोंग
	3. रमटेक
16. तमिलनाडु	1. कावेरीपट्टीनाम
17. उत्तर प्रदेश	1. कुशीनगर
	2. पिपरहवा
	3. संकासिया
	4. सारनाथ
	5. श्रावस्ती

Merger of DA with basic pay for central Government employees

*348. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had accepted the recommendation of the last Pay Commission to merge the dearness allowance of the Central Government employees with their basic pay if it exceeded 50 percent of their basic pay;

(b) whether it is also a fact that the present percentage of DA has crossed the limit perscribed by the Pay Commission; and

(c) if so, by when a final decision in regard to the merger of D.A. with basic pay is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) No such recommendation has been made by the 4th Central Pay Commission.

(b) Does not arise.

(c) Demand of the Staff Side to treat a portion of Dearness Allowance as pay was discussed in the last meeting of the National Council of the JCM held on the

21st September, 1991. The Council decided to remit the matter to a committee comprising representatives from the Staff Side and the Official Side. The matter is now before the Committee and its report is awaited.

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव

*349. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में इस समय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इनमें से ग्रेडवार कितने-कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) अनुसूचित जनजाति के ग्रेडवार कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पदोन्नति के समय इन श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इन आरोपों से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार है:—

(वैकल्पिक सूचना)

संवर्ग	कुल संख्या	प्रतिनिधित्व		अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
अधिकारी	1470	125	49	1
लिपिक	3528	550	238	20
अधीनस्थ स्टाफ (सफाई कर्मचारियों सहित)	1605	355	191	14

(ग) जी नहीं।

(घ) बैंक के किसी अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी से पदोन्नति न किए जाने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की योजनाएं

*350. **श्री राघवजी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदिशा (मध्य प्रदेश) जिले के शहरों में डाक-तार विभाग और टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनायी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां। डाक विभाग का मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोंज और गंज बसोदा कस्बों में, प्रत्येक में दो-दो मकान बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) ये मकान टाइप-II श्रेणी के होंगे और ऐसी संभावना है कि ये 1993-94 के दौरान बन जाएगें।

(ग) जहां तक डाक विभाग का संबंध है उपर्युक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, मध्य प्रदेश में विदिशा में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए एक एकड़ जमीन ली जा रही है। वहां लगभग दस (10) स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में चाय की पैदावार करने की योजना

*351. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अमरकंटक, बस्तर और मंचमढ़ी में चाय की पैदावार करने की कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों में से किस स्थान पर चाय की पैदावार की गई है और पैदावार की मात्रा क्या रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो तो क्या सरकार द्वारा चाय बनाने के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर उक्त स्थानों पर चाय की